

केंद्र के खिलाफ राज्यों की बढ़ती अपील से सर्वोच्च न्यायालय चतिति

प्रलिमिंस के लिये:

[सर्वोच्च न्यायालय](#), [राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष \(NDRF\)](#), [आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005](#), [राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष](#)

मेन्स के लिये:

आपदा प्रबंधन, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, राज्य उधार लेने की शक्ति, केंद्र-राज्य संबंध

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

[भारत के सर्वोच्च न्यायालय](#) ने राज्यों द्वारा केंद्र के खिलाफ उसके पास जाने के लिये मजबूर होने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चर्चा व्यक्त की है।

कनि मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी?

■ तमलिनाडु:

- तमलिनाडु ने केंद्र पर लगभग 38,000 करोड़ रुपए की आपदा राहत नधि में देरी करके राज्य की ज़रूरतों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया।

■ केरल:

- केरल ने सीधे सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें केंद्र पर उसकी 'नेट बॉरोइंग सीलिंग' (2023-24 के लिये अनुमानित [सकल राज्य घरेलू उत्पाद](#) के 3% के रूप में नरिधारति) में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया, जिससे राज्य [कोवत्तीय आपातकाल](#) की ओर अग्रसर कर दिया गया।

■ कर्नाटक:

- मानवीय संकट से निपटने के लिये राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (National Disaster Response Fund- NDRF) के तहत कर्नाटक का ₹18,171.44 करोड़ का अनुरोध छह महीने से अनुत्तरति है।
- राज्य का तर्क है कि केंद्र की नषिक्रयिता न केवल [आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005](#) के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है, बल्कि [भारत के संविधान](#) के तहत गारंटीकृत राज्य के लोगों के [मौलिक अधिकारों](#) का भी उल्लंघन करती है, जिसमें [समानता और जीवन का अधिकार](#) भी शामिल है।
 - राज्य गंभीर सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है, जिससे वर्षा में भारी कमी हो रही है, जिससे लोगों का जीवन प्रभावति हो रहा है।

राज्यों द्वारा राजस्व उधार लेने और केंद्र के साथ विवाद निपटारे हेतु संविधानिक प्रावधान क्या हैं?

■ अनुच्छेद 293:

- इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन, किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति, भारत के क्षेत्र के अंतर्गत राज्य की संचति नधिकी सुरक्षा पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हो, ऋण लेने तक वसितारति है, जो समय-समय पर वधियिका द्वारा तय की जा सकती है।
- भारत सरकार संसद द्वारा नरिधारति शर्तों के अधीन राज्यों को ऋण दे सकती है या गारंटी प्रदान कर सकती है।
- यदि भारत सरकार के पछिले ऋण का कोई हिस्सा बकाया रहता है तो [राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना ऋण नहीं उठा सकते हैं](#)।
 - यदि आवश्यक हो तो भारत सरकार द्वारा शर्तों के साथ उधार लेने की सहमति दी जा सकती है।

■ अनुच्छेद 131:

- यह [सर्वोच्च न्यायालय](#) के मूल कषेत्राधिकार से संबंधति है। इसका मतलब यह है कि यह [सर्वोच्च न्यायालय](#) को नमिनलखिति के बीच विवादों को सीधे सुनने और नरिणय लेने का अधिकार देता है:
 - केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारें।

- दो या दो से अधिक राज्य सरकारें ।
- अनविरय रूप से यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच या स्वयं विभिन्न राज्य सरकारों के बीच असहमतियों में रेफरी/नरिणायक के रूप में कार्य करता है ।

भारत की शासन व्यवस्था में केंद्र-राज्य संबंध	अवस्था	संवैधानिक प्रावधान	प्रमुख विशेषताएँ
वधायी संबंध		अनुच्छेद 245 से 255	<ul style="list-style-type: none"> ■ संसद के पास राज्य विधानमंडलों के लिये अत्यधिक वधायी शक्तियाँ होती हैं । ■ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में वषियों की रूपरेखा । ■ सूचियों में शामिल नहीं किये गए कसि भी वषिय पर कानून बनाने का संसद का वषिष अधिकार ।
प्रशासनिक संबंध		अनुच्छेद 256 से 263	<ul style="list-style-type: none"> ■ राज्यों को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना आवश्यक है । ■ प्रशासनिक मामलों में "सहकारी संघवाद" की अवधारणा । ■ कुछ मामलों पर राज्यों को नरिदेश देने की केंद्र की शक्ति ।
वत्तीय संबंध		अनुच्छेद 264 से 293	<ul style="list-style-type: none"> ■ केंद्र और राज्यों के बीच कराधान शक्तियों का वभिजन । ■ कर लगाने और उसके वभिजन के नियम । ■ राज्यों को वत्तीय अनुदान और संसाधन अंतरण के प्रावधान ।

राज्यों के लिये आपदा बहाली योजनाओं में केंद्र सरकार की क्या भूमिका है?

■ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005:

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 आपदा प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय, राज्य, ज़िला और स्थानीय स्तर पर संस्थागत, कानूनी, वत्तीय एवं समन्वय तंत्र नरिधारित करता है ।
 - यह अधिनियम आपदा प्रबंधन प्रयासों की देखरेख और कार्यान्वयन के लिये [राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण \(NDMA\)](#) एवं राज्य तथा ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसे विभिन्न प्राधिकरणों व समितियों की स्थापना को अनविरय करता है ।
- यह अधिनियम केंद्र सरकार को आपदा प्रबंधन में सुवधि या सहायता के लिये **NDMA, राज्य सरकारों/SDMA**, या उनके कसि भी अधिकारी/कर्मचारी को नरिदेश जारी करने का अधिकार देता है ।
- **वत्ति आयोग** आपदा प्रतिक्रिया के साथ-साथ आपदा शमन के लिये धन के नरिमाण की सफिराशि करता है, जसि अब एक साथराष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (NDRMF) और राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (SDRMF) कहा जाएगा ।
 - 15वें वत्ति आयोग ने वर्ष 2021-26 की अवधि के लिये **राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF)** की सफिराशि की, तथा NDMF के साथ-साथ **राज्य DMF** की स्थापना की गई है ।
 - SDRMF में केंद्र व राज्य दोनों सरकारों द्वारा योगदान दिया जाता है, सामान्य राज्यों के लिये **75:25 अनुपात** और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिये **90:10 अनुपात** नरिधारित होता है ।

■ राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF):

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित **SDRF**, अधिसूचित आपदाओं की प्रतिक्रिया के लिये राज्य सरकारों के पास उपलब्ध प्राथमिक नधि है ।
 - केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिये **SDRF आवंटन का 75%** तथा वषिष श्रेणी के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (पूर्वोत्तर राज्यों, सकिकिम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर) के लिये **90%** का योगदान करती है ।
- वत्ति आयोग की सफिराशि के अनुसार वार्षिक केंद्रीय योगदान दो समान कशितों में जारी कया जाता है ।
- SDRF का उपयोग केवल पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के वयय को पूरा करने के लिये कया जाएगा ।
 - **SDRF के अंतरगत आने वाली आपदाएँ:** चक्रवात, सुखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृषटि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट हमला, ठंड और टंडी लहरें ।

■ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF):

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 के तहत स्थापित NDRF, खतरनाक स्थितियों या आपदाओं के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास को संबोधित करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित एक कोष है ।

- यह गंभीर प्रकृतिक आपदा की स्थिति में राज्य के SDRF को पूरक बनाता है, बशर्ते SDRF में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न हो।
- इस कोष को भारत सरकार के "सार्वजनिक खाते" में "ब्याज न देने वाली आरक्षण कोष" के अंतर्गत रखा जाता है, जिससे सरकार इसे संसदीय अनुमोदन के बिना उपयोग करने में सक्षम बनाती है।
 - NDRF को उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के अधीन वशिष्ट वस्तुओं पर लगाए गए उपकर के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जिसे वित्त वधियक के माध्यम से वार्षिक तौर पर मंजूरी दी जाती है।
- NDRF आवंटन से परे अतिरिक्त कोषीय आवश्यकताओं को सामान्य बजटीय संसाधनों के माध्यम से पूरण किया जाता है, जिससे आपदा राहत प्रयासों के लिये निरंतर समर्थन सुनिश्चित होता है।
- कोष के उपयोग की नगिरानी NDMA की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) द्वारा की जाती है, जिसमें पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा वार्षिक ऑडिट किया जाता है।

वित्तीय सहायता के वितरण के संबंध में राज्यों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

- **वलिंबति एवं अपर्याप्त आपदा राहत:**
 - आपदा प्रबंधन नधि (NDRF तथा SDRF) के वितरण में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय का अभाव।
 - आपदा सहायता की मात्रा निर्धारित करने में केंद्र के एकतरफा नरिणय लेने पर चर्चा।
 - राज्यों को आपदा राहत एवं पुनर्वास सहायता की मात्रा निर्धारित करने के लिये केंद्र के पासस्पष्ट, पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण मानदंडों का अभाव।
 - आपदा सहायता पर केंद्र के नरिणयों को चुनौती देने के लिये राज्यों के पास पर्याप्त संस्थागत तंत्र का अभाव।
- **केंद्र-राज्य आपदा प्रबंधन ढाँचे में असंतुलन:**
 - आपदा प्रबंधन शक्तियों एवं नरिणय लेने के अधिकार के संदर्भ में केंद्र के पास अति-केंद्रीकरण।
 - NDMA के केंद्र पर अत्यधिक निर्भर होने तथा राज्यों के प्रभावी प्रतिनिधित्व की कमी को लेकर चर्चाएँ हैं।
 - राज्यों के पास अपने स्थानीय संदर्भों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार, आपदा प्रतिक्रिया तथा शमन उपायों को अनुकूलित करने हेतु लचीलेपन का अभाव है।
- **केंद्रीकृत योजना:**
 - केंद्रीकृत योजना हमेशा प्रत्येक राज्य की वशिष्ट आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रख सकती है, जिससे आपदाओं अथवा सहायता की आवश्यकता वाली अन्य स्थितियों की प्रतिक्रिया में अक्षमताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **राजनीतिक गतिशीलता:**
 - केंद्र सरकार तथा राज्यों के बीच राजनीतिक गतिशीलता एवं संबंधों में सहायता वितरण को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे कभी-कभी पूरवाग्रह अथवा पक्षपात के आरोप भी लग सकते हैं।
- **परामर्श का अभाव:**
 - केंद्र पर प्रायः नीतियों तथा योजनाओं को तैयार करते समय राज्यों से परामर्श नहीं करने का आरोप लगाया जाता है, जिससे योजनाओं के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
 - केंद्र द्वारा राज्यों की सहमतिका बिना उन पर एकतरफा नरिणय थोपना भी उदाहरण टकराव का एक स्रोत रहे हैं।
 - केंद्र और राज्यों के बीच नयिमति संवाद एवं विवाद समाधान हेतु प्रभावी संस्थागत मंचों का अभाव।
 - बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मक एवं प्रतिकूल राजनीति के सामने संघीय भावना तथा सहयोगात्मक दृष्टिकोण का कमजोर होना।

आगे की राह

- कराधान शक्तियों एवं राजस्व बँटवारे की समीक्षा करके, राजकोषीय असंतुलन को दूर करके राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देना।
- केंद्र और राज्यों के बीच नयिमति संवाद एवं आम सहमतिकाबिना के लिये संस्थागत मंचों को पुनर्जीवित करना। केंद्र-राज्य विवादों को संबोधित करने हेतु सहयोगात्मक नीति निर्धारण तथा प्रभावी विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना।
- आपदा राहत नधि एवं सहायता उपयोग हेतु नरिणय लेने में पारदर्शिता में सुधार करना। नधि के गबन तथा भेदभाव को रोकने के लिये लेखापरीक्षा एवं नरिक्षण बढ़ाना।
- एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा देना जो पक्षपातपूर्ण एजेंडे पर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देती है तथा केंद्र और राज्य स्तरों के बीच सहयोग एवं पारस्परिक सम्मान बढ़ाने को प्रोत्साहित करती है। प्रभावी शासन तथा न्यायसंगत विकास के लिये सहकारी संघवाद के महत्त्व के बारे में नागरिकों को शक्ति करती है।

दृष्टिमुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. राजनीतिक गतिशीलता एवं अपर्याप्त परामर्श संकट के समय केंद्र-राज्य को सहयोग करने से कैसे रोकते हैं, और अधिक सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने के लिये क्या बदलाव किये जाने चाहिये?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. नमिन्लखिति में से कौन-सी एक भारतीय संघराज्य पद्धतिकी विशेषता नहीं है? (2017)

- (a) भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है।
- (b) केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट वभाजन किया गया है।
- (c) संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्य सभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है।
- (d) यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है।

उत्तर: (d)

प्रश्न. स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है: (2017)

- (a) संघवाद का
- (b) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का
- (c) प्रशासनिक प्रत्यायोजन का
- (d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र का

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. पहले के प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण से हटकर भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु शुरू किया गए हालिया उपायों की चर्चा कीजिये। (2020)

प्रश्न. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में उत्तराखंड के कई स्थानों पर हाल ही में बादल फटने की घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिये अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा कीजिये। (2016)

चुनाव उम्मीदवार की नजिता का अधिकार

प्रलिस के लिये:

[सर्वोच्च न्यायालय](#), [नरिवाचन आयोग](#), [नजिता का अधिकार](#), [जन प्रतिनिधित्व अधिनियम \(RPA\), 1951](#)

मेन्स के लिये:

चुनावी प्रक्रिया में नजिता के अधिकार एवं पारदर्शिता के बीच संतुलन, चुनावी सुधार, चुनावों को अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना।

स्रोत: द हट्टि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने नरिणय दिया है कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को उसके पास मौजूद प्रत्येक चल संपत्तिकी घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है।

- न्यायालय ने नरिणय दिया कि उम्मीदवार अपने जीवन के प्रत्येक विवरण को जाँच के लिये उजागर नहीं कर सकते हैं और उनके पास भी मतदाताओं के समान ही [नजिता का भी अधिकार](#) है।

मामले से जुड़े मुख्य तथ्य क्या हैं?

- सर्वोच्च न्यायालय, अरुणाचल प्रदेश के एक विधायक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें वर्ष 2023 के गुवाहाटी [उच्च न्यायालय](#) के नरिणय को चुनौती दी गई थी, जिसमें 1961 के चुनाव संचालन नियमों के साथ संलग्न फॉर्म में दायर अपने हलफनामे में तीन वाहनों को अपनी संपत्तिके रूप में घोषित नहीं करने के कारण उनके चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया गया था।
- याचिका में कहा गया है कि चुनावी उम्मीदवार ने उक्त वाहनों के स्वामित्व की घोषणा नहीं की जिस कारण उसे [जन प्रतिनिधित्व अधिनियम \(RPA\)](#),

1951 की धारा 123 के तहत "भ्रष्ट आचरण" का माना गया।

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी उम्मीदवार द्वारा उन मामलों पर अपनी गोपनीयता बनाए रखने का वकिलप जो मतदाताओं के लिये कोई चिंता का विषय नहीं थे अथवा सार्वजनिक पद हेतु उसकी उम्मीदवारी के लिये अप्रासंगिक थे, **RRA, 1951** की धारा 123 के तहत "भ्रष्ट आचरण" नहीं है।
 - साथ ही इस तरह का गैर-प्रकटीकरण 1951 अधिनियम की धारा 36(4) के तहत "महत्त्वपूर्ण प्रकृतिका दोष" नहीं माना जाएगा।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मतदाताओं को उस जानकारी का खुलासा करने का अधिकार है जो उस उम्मीदवार को चुनने के लिये आवश्यक है जिसके लिये वोट डाला जाना चाहिये।

नजिता का अधिकार क्या है?

- नजिता का अधिकार एक **मौलिक अधिकार** है, जो व्यक्ति को राज्य और गैर-राज्य दोनों तत्त्वों के हस्तक्षेप से बचाता है तथा व्यक्ति को स्वायत्त जीवन वकिलप चुनने की अनुमति देता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में **के.एस. पुट्टासवामी बनाम भारत संघ** के ऐतिहासिक नरिणय में नजिता एवं उसके महत्त्व का वर्णन करते हुए कहा कि नजिता का अधिकार एक मौलिक व अवभाज्य अधिकार है और यह उस व्यक्ति से जुड़ा है जिसमें उस व्यक्ति तथा उसके द्वारा चुने गए वकिलपों के बारे में संपूर्ण जानकारी शामिल है।
- नजिता का अधिकार **अनुच्छेद 21** के तहत **जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग** के रूप में संरक्षित है।

RPA 1951 और अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण क्या है?

- **परिचय:**
 - वर्ष 1951 का RPA नरिवाचन के संचालन और नरिवाचन प्रतनिधियों की योग्यता व अयोग्यता को नरिंतरि करता है।
- **प्रावधान:**
 - यह **नरिवाचन के संचालन** को नरिंतरि करता है।
 - यह संसद के विधायी सदन की **सदस्यता के लिये योग्यता और अयोग्यताएँ नरिदषि** करता है,
 - यह भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने का भी प्रावधान करता है।
 - यह नरिवाचन से उत्पन्न होने वाले संदेहों और विवादों को नरिपटाने की प्रक्रिया नरिधारि करता है।
 - **1951 के अधिनियम की धारा 36(4)** में उल्लेख है कि ररिर्नगि अधिकारी किसी भी दोष के आधार पर किसी भी नामांकन पत्र को अस्वीकार नहीं करेगा जो सही चरतिर का नहीं है।
- **RPA, 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण:**
 - **भ्रष्ट आचरण:** अधिनियम की धारा 123 'भ्रष्ट आचरण' को परिभाषि करती है जिसमें **रशिवतखोरी, अनुचति प्रभाव, गलत जानकारी** और नरिवाचन में अपनी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिये एक उम्मीदवार द्वारा "धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं" को बढ़ावा देना।
 - **अभरिास सहि बनाम सी. डी. कॉमाचेन मामले (2017)** में सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय सुनाया कि उम्मीदवारों को न केवल अपने धर्म के आधार पर बल्कि मतदाताओं के धर्म के आधार पर भी वोट की अपील करने से प्रतबिधति कयि गया है।
 - **अनुचति प्रभाव:** यह धारा अनुचति प्रभाव को धमकियों सहति किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप के रूप में परिभाषि करती है, जो चुनावी अधिकारों के स्वतंत्र अभ्यास में बाधा डालती है।
 - **अयोग्यता:** धारा 123(4) कुछ अपराधों, भ्रष्ट आचरण, चुनावी खर्र्चों की घोषणा करने में वफिलता, या सरकारी अनुबंधों या कार्यों में रुचिरखने के लिये एक नरिवाचन प्रतनिधि को अयोग्य घोषति करने की अनुमति देती है।
- **महत्त्व:**
 - यह अधिनियम भारतीय लोकतंत्र के सुचारू कामकाज के लिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के प्रतनिधि नकियों में प्रवेश पर रोक लगाता है, और इस प्रकार **भारतीय राजनीति को अपराधमुक्त** कर देता है।
 - अधिनियम के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करनी होगी तथा चुनाव के खर्र्चों का लेखा-जोखा रखना होगा।
 - यह प्रावधान सार्वजनिक धन के उपयोग में उम्मीदवार की जवाबदेही और पारदर्शति सुनश्चति करता है।
 - यह **बूथ कैपचरगि, रशिवतखोरी या शत्रुता** को बढ़ावा देने आदि जैसी भ्रष्ट प्रथाओं पर रोक लगाता है, जो चुनावों की वैधता और स्वतंत्र व नषिपक्ष आचरण सुनश्चति करती हैं।
 - अधिनियम में प्रावधान है कि केवल वे राजनीतिक दल जो **RPA अधिनियम, 1951 की धारा 29A** के तहत पंजीकृत हैं, चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने के पात्र हैं, और चुनावी फंडगि में पारदर्शति सुनश्चति करते हैं।

दृष्टिमुख्य प्रश्न:

प्रश्न. संपत्ति के प्रकटीकरण के संबंध में चुनाव उम्मीदवारों की नजिता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया नरिणय के नरिहितार्थ पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. 'नजिता का अधकार' भारत के संवधान के कसि अनुच्छेद के तहत संरक्षित है?

- (a) अनुच्छेद 15
- (b) अनुच्छेद 19
- (c) अनुच्छेद 21
- (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (c)

प्रश्न 2. नजिता के अधकार को जीवन एवं व्यक्तगत स्वतंत्रता के अधकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित कया जाता है। भारत के संवधान में नमिनलखित में से कसिसे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थति होता है? (2018)

- (a) अनुच्छेद 14 एवं संवधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध।
- (b) अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दयि राज्य के नीता के नरिदेशक तत्त्व।
- (c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ।
- (d) अनुच्छेद 24 एवं संवधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध।

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. नजिता के अधकार पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम नरणय के आलोक में मौलकि अधकारों के वसितार का परीक्षण कीजयि। (2017)

प्रश्न. "लोक प्रतनिधितिव अधनियिम के अंतरगत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रया के सरलीकरण की आवश्यकता है"। टपिपणी कीजयि। (2020)

भारत का जनसांख्यिकीय संक्रमण

प्रलिमिस के लयि:

[जनसांख्यिकीय लाभांश](#), [कुल प्रजनन दर \(TFR\)](#), [महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी \(मनरेगा\)](#), एशया 2050 रपिर्ट।

मेन्स के लयि:

भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन, भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का महत्त्व, भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश से जुड़ी चुनौतियाँ।

[सरोत: इंडयिन ऐक्सपरेस](#)

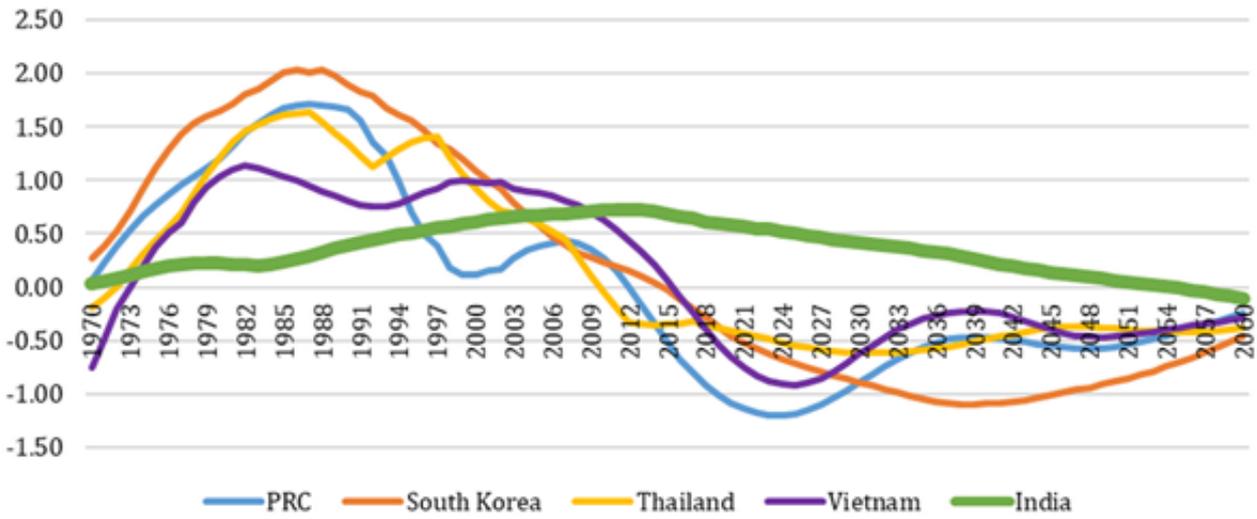
चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के अनुसार, भारत की जनसंख्या वृद्धि एक प्रमुख फोकस रही है, जसिकेवर्ष 2065 तक 1.7 बलियिन तक पहुँचने का अनुमान है, जो भारत में [जनसांख्यिकीय लाभांश](#) के चल रहे संक्रमण को रेखांकित करता है।

- यह एक महत्त्वपूर्ण लेकनि कम चर्चति पहलू पर ध्यान स्थानांतरति करता है, **प्रजनन दर में गरिावट**, जसिके **लैसेट रपिर्ट** के अनुसार वर्ष 2051 तक 1.29 तक जाने का अनुमान है।

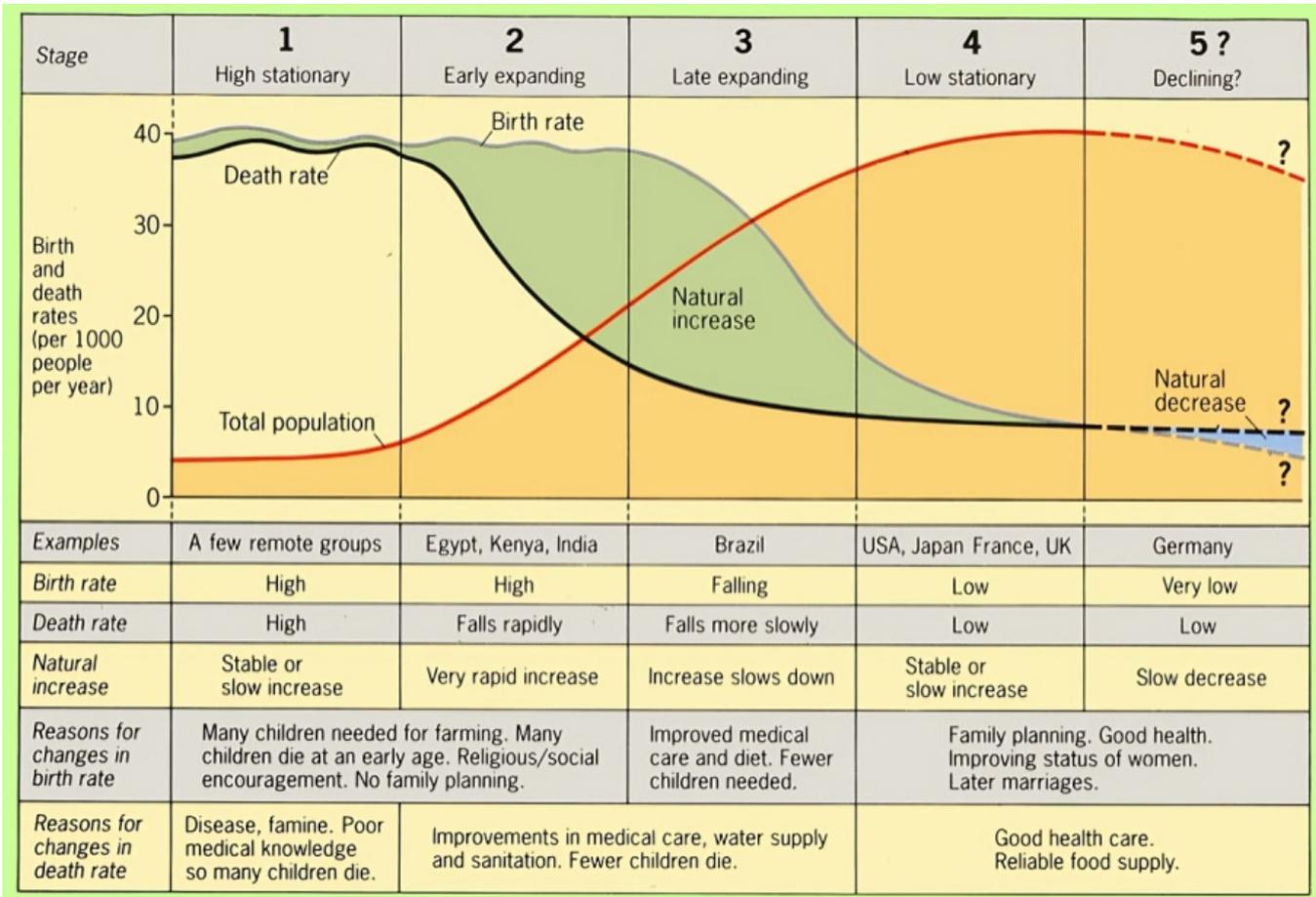
- वर्ष 2021-2025 (1.94) तथा वर्ष 2031-2035 (1.73) की अवधि के लिये सरकार की अनुमानित [कुल प्रजनन दर \(TFR\)](#) [लैंसेट अध्ययन](#) और [NFHS 5 डेटा](#) के अनुमान से अधिक है।
- इससे पता चलता है कि भारत की जनसंख्या वर्ष 2065 से पहले 1.7 बिलियन से नीचे स्थिर हो सकती है।

Demographic Dividend: India vs. Others



जनसांख्यिकीय संक्रमण और जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है?

- जनसांख्यिकीय संक्रमण का तात्पर्य समय के साथ जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन से है।
 - यह परिवर्तन विभिन्न कारणों के कारण हो सकता है जैसे जन्म दर तथा मृत्युदर में परिवर्तन, प्रवासन प्रक्रिया तथा सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश** एक ऐसी घटना है जो तब होती है जब किसी देश की जनसंख्या संरचना आश्रितों (बच्चों और बुजुर्गों) के उच्च अनुपात से काम करने वाले वयस्कों के उच्च अनुपात के रूप में स्थानांतरित हो जाती है।
 - यदि देश मानव पूंजी में निवेश और उत्पादक रोजगार हेतु स्थितियों का निर्माण करता है, तो जनसंख्या संरचना में इस बदलाव का परिणाम आर्थिक वृद्धि और विकास का कारक हो सकता है।



भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन के लिए कौन से कारक ज़िम्मेदार हैं?

- **तीव्र आर्थिक विकास:**
 - आर्थिक विकास की गति, विशेष रूप से 21वीं सदी के शुरुआती वर्षों से, जनसांख्यिकीय परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चालक रही है।
 - आर्थिक विकास से जीवन स्तर में सुधार, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ और शिक्षा तक पहुँच में वृद्धि होती है, जो सामूहिक रूप से नमिन प्रजनन दर में योगदान करती है।
- **शिशु एवं बाल मृत्यु दर में कमी:**
 - शिशुओं और बच्चों के बीच कम मृत्यु दर ने परिवारों को वृद्धावस्था में सहायता के लिये बड़ी संख्या में बच्चे रखने की आवश्यकता को कम कर दिया है।
 - जैसे-जैसे स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार हुआ है, वैसे ही बाल मृत्यु दर में कमी आई है।
- **महिला शिक्षा और कार्य भागीदारी दर में वृद्धि:**
 - बढ़ती शिक्षा और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
 - जैसे-जैसे महिलाएँ अधिक शक्ति एवं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती जाती हैं, उनके कम बच्चे होते हैं और बच्चे के जन्म में देरी होती है, जिससे कुल प्रजनन दर में गिरावट आई है।
- **आवास स्थितियों में सुधार:**
 - बेहतर आवास स्थितियों और बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच जीवन की गुणवत्ता में सुधार में योगदान करती है, जो बदले में परिवार नियोजन नरिणियों को प्रभावित करती है।
 - परिवार छोटे होने पर वह बेहतर तरीके से रहने की स्थितिका विकल्प भी चुन सकता है।

भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियाँ क्या हैं?

- **नरिभरता अनुपात परिवर्तन:**
 - हालाँकि शुरुआत में TFR में गिरावट से नरिभरता अनुपात में गिरावट आती है और कामकाजी उम्र की आबादी में वृद्धि होती है, लेकिन अंततः इसके परिणामस्वरूप वृद्ध आश्रितों की हसिसेदारी बढ़ जाती है।
 - यह चीन, जापान और यूरोपीय देशों में देखी गई स्थितियों के समान, स्वास्थ्य देखभाल एवं सामाजिक कल्याण के लिये संसाधनों पर दबाव डालता है।
- **राज्यों में असमान परिवर्तन:**

- (a) जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात ।
(b) इसके भवनों, अन्य आधारित संरचना और मशीनों का स्टॉक ।
(c) कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का आकार ।
(d) समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर ।

उत्तर: (d)

प्रश्न. भारत को "जनसांख्यिकीय लाभांश" वाला देश माना जाता है । इसकी वज़ह है: (2011)

- (a) इसकी 15 वर्ष से कम आयु वर्ग में उच्च जनसंख्या ।
(b) इसकी 15-64 वर्ष के आयु वर्ग की उच्च जनसंख्या ।
(c) इसकी 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की उच्च जनसंख्या ।
(d) इसकी कुल उच्च जनसंख्या ।

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर वस्तुतः प्रकाश डालिये । (2021)

प्रश्न. "महिला सशक्तीकरण जनसंख्या संवृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है ।" चर्चा कीजिये । (2019)

प्रश्न. समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिये कि क्या बढ़ती हुई जनसंख्या नरिधनता का मुख्य कारण है या नरिधनता जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है । (2015)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/13-04-2024/print>

